जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 | वर्षः 51 | संख्याः 275 | प्रभात | कोटा, रविवार 19 जुलाई, 2026 | कोटा/24/2012-14 | पृष्ठ 8 | मूल्य 2.50 रु.

सफेद चादरों की ओट में वांगचुक को उठा ले गई दिल्ली पुलिस

दिल्ली पुलिस नहीं चाहती थी कि उसकी कार्यवाही का कोई टीवी कवरेज हो या कोई फोटो खिंचे

- सूत्रों ने कहा, एक दिन पहले ही नियुक्त हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार को पहला टास्क यही सौंपा गया था कि वांगचुक को अस्पताल ले जाया जाए और भोजन दिया जाए, चाहे इसमें जबर्दस्ती ही क्यों ना करनी पड़े।
- हालांकि सोनम ने अस्पताल में ट्यूब्स के जरिए तरल पदार्थ लेने से इन्कार कर दिया है।
- सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशनरत हैं पर अभी तक सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया या चिंता नहीं जताई है।
- 20 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरु हो रहा है, सोनम ने युवा वर्ग व छात्रों से संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है सरकार ने भी इस मार्च को रोकने के लिए कमर कस ली है।
- आगामी संसद सत्र में सोनम वांगचुक और पेपर लीक के मुद्दे पर भारी हंगामा होने की संभावना है।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। लोकतंत्र के लिए शर्मनाक और बड़ा झटका माने जा रहे घटनाक्रम में दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पहुंची और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को जबरन उठाकर अस्पताल ले गई, जिससे उनका अनशन समाप्त कराया जा सके।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दिल्ली पुलिस अपने साथ सफेद चादरें लेकर पहुंची थी, ताकि कार्रवाई के दौरान तस्वीरें न ली जा सकें। पुलिसकर्मियों ने सफेद चादरों की ओट बनाली और, वांगचुक के विरोध के बावजूद, उन्हें जबरन उठाकर वहां से ले गए।

वहां मौजूद सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने इसका भारी विरोध किया, लेकिन सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने अपनी कार्यवाही जारी रखी और वांगचुक को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया।

बताया गया कि इससे एक शाम पहले ही डॉक्टरों ने कहा था कि वांगचुक के सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संकेत (वाइटल्स) स्थिर हैं और उनकी स्थिति अच्छी है।

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने घोषणा की है कि आंदोलन जारी रहेगा और अब वे स्वयं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होने तक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

एक दिन पहले ही दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त की नियुक्ति हुई थी और उनका पहला बड़ा कदम यह सुनिश्चित करना था कि छात्रों और जैन ज़ी के आक्रोश तथा विरोध प्रदर्शनों का केन्द्र बन चुके सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाकर अस्पताल ले जाया जाए तथा उनकी जान बचाने के नाम पर उन्हें जबरन भोजन कराया जाए। 20 दिनों से जारी इस भूख हड़ताल के दौरान सरकार पूरी तरह असंवेदनशील और निष्क्रिय बनी रही है, न तो कोई मंत्री और न ही सरकार का कोई प्रतिनिधि वांगचुक या प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने पहुंचा। यदि वांगचुक के साथ कोई अनहोनी हो जाती, तो पूरे देश में ऐसा जनाक्रोश भड़क सकता था, जिसे सरकार के लिए नियंत्रित करना बेहद कठिन होगा।

20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी और देशभर से हजारों युवा संसद तक मार्च निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उनका उद्देश्य शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाना है। क्योंकि उनके कार्यकाल में बार-बार प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन न तो उन्होंने और न ही सरकार के किसी अन्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमरनाथ यात्रा स्थगित

श्रीनगर, 18 जुलाई। मौसम विभाग द्वारा खराब मौसम की चेतावनी जारी किए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने एहतियातन बड़ा कदम उठाया है। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा को 19 जुलाई, 2026 से दोनों मार्गों पहलगाम और बालटाल से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है।

कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने शनिवार को इस फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि भारत मौसम

- मौसम विभाग ने भारी वर्षा, भूस्खलन व अचानक बाढ़ की चेतावनी दी है।

विज्ञान विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में भारी बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। इस वजह से रविवार, 19 जुलाई से बालटाल और नुनवान/चंदनवाड़ी (पहलगाम) दोनों ही बेस कैंपों से किसी भी श्रद्धालु को पवित्र गुफा की तरफ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह निलंबन पूरी तरह से एक एहतियाती कदम है ताकि पहाड़ी रास्तों पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह के मौसम जनित खतरे का सामना न करना पड़े। मौसम साफ होने और पूरे यात्रा मार्ग की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा करने के बाद ही यात्रा दोबारा बहाल करने पर फैसला लिया जाएगा। यात्रा दोबारा शुरू होने के संबंध में जल्द ही ताजा अपडेट जारी किए जाएंगे। प्रशासन ने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि वे मौसम के मिजाज को देखते हुए आधिकारिक दिशा-निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग दें।

अरब देश ईरानी हमलों के खिलाफ रुसी एयर डिफैंस सिस्टम लगाने की तैयारी में हैं

क्योंकि अमेरिका के साथ शत्रुता के चलते ईरान अरब देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों व अमेरिकन डिफैंस सिस्टम को निशाना बना रहा है

- अरब देशों के अनुसार, ईरान की रुस से गहरी मित्रता है और अगर अरब देशों में रुस का एस-400 एयर डिफैंस सिस्टम लगाया गया तो ईरान शायद हमला न करे।
- अरब देशों पर ईरान के हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा है। प्रारंभ से ही अरब देशों व ईरान के बीच तनाव रहा है, इसका कारण है कि ईरान खुद को पर्शियन मूल का मानता है और अरबों को खुद से निम्न स्तर पर रखता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। ईरान और फ़ारस की खाड़ी के उसके पड़ोसी देशों के लिए यह समय "म्युचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन" (पारस्परिक सुनिश्चित विनाश) का समय बन गया है। इसका परिणाम यह है कि ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच पहले से मौजूद अविश्वास अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है।

इन बदलते हालात में, फ़ारस की खाड़ी के अरब देश अमेरिका से अलग अपनी खुद की स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना चाहते हैं। ये देश ईरान के हवाई हमलों से बचाव के लिए रूस की एस-400 एयर डिफैंस सिस्टम तैनात करना चाहते हैं।

खाड़ी के अरब देश तुर्किये से ये रक्षा प्रणालियां हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुर्किये के पास ये प्रणालियां मौजूद हैं। लेकिन रूस की मंजूरी के बिना तुर्किये इन्हें किसी दूसरे देश को नहीं बेच सकता। यही सबसे बड़ी समस्या है।

रूस ईरान के प्रति सहानुभूति रखता है, क्योंकि ईरान अमेरिका से लड़ रहा है, जो नाटो के नेतृत्व वाले पश्चिमी गठबंधन का हिस्सा है। इसलिए रूस के लिए यह फैसला मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर, रूस के लिए यह धन जुटाने तथा और अधिक अंतरराष्ट्रीय समर्थन हासिल करने का एक बहुत अच्छा अवसर भी है।

जैसे-जैसे डॉनल्ड ट्रंप ने ईरान और उसकी रणनीतिक संपत्तियों पर अपने हमले तेज किए हैं, ईरान अपना गुस्सा फ़ारस की खाड़ी के अरब देशों पर निकाल रहा है। ईरान जवाबी कार्यवाही में बहरीन, क़तर, कुवैत और सऊदी अरब और अब जॉर्डन और सीरिया पर भी हमले तेज कर रहा है।

ईरान ने कहा है कि वह पड़ोसी देशों पर अपनी बमबारी और तेज करेगा, क्योंकि अमेरिकी मुख्य भूमि उसके मिसाइलों की पहुँच से बहुत दूर है। इन देशों में अमेरिका की महत्वपूर्ण सैन्य सुविधाएं मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल ईरानी ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के लिए किया गया है।

पिछले दो दिनों में कुवैत ने अपने बिजली उत्पादन संयंत्रों और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले कुछ महत्वपूर्ण संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचने की जानकारी दी है। इससे ईरान और उसके अरब पड़ोसियों के बीच गंभीर तनाव पैदा हो गया है, जिसका असर दूर-दराज़ के क्षेत्रों तक फैल रहा है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत ने पहला प्राइवेट रॉकेट, विक्रम- प्रथम लॉंच किया

यह रॉकेट हैदराबाद के स्टार्ट अप स्कायरुट एयरोस्पेस ने बनाया है

- यह रॉकेट लो अर्थ ऑर्बिट में छोटे उपग्रह स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है और 18 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सैंटर से इसे अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया।

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 18 जुलाई। भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए देश के निजी तौर पर विकसित पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का सफल प्रक्षेपण कर दिया है। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप "स्कायरूट एयरोस्पेस" द्वारा विकसित इस रॉकेट का प्रक्षेपण 18 जुलाई को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से मिशन आगमन के तहत किया गया।

इस प्रक्षेपण के साथ भारत की एक निजी कंपनी ने पहली बार ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बाजार में प्रवेश किया है, जिस पर अब तक मुख्य रूप से सरकारी अंतरिक्ष अभियानों का वर्चस्व रहा है। विक्रम-1 "लो अर्थ ऑबिट" (एल ई ओ) को निम्न पृथ्वी कक्षा (लो अर्थ ऑर्बिट-एलईओ) में छोटे उपग्रह स्थापित करने के लिए विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य तेज़ तथा अधिक लचीली वाणिज्यिक प्रक्षेपण सेवाएं उपलब्ध कराना है।

स्कायरूट एयरोस्पेस के सह-संस्थापक पवन कुमार चंदना ने बताया कि इस मिशन का नाम आगमन इसलिए रखा गया क्योंकि कंपनी परीक्षण उड़ानों से आगे बढ़कर अब वाणिज्यिक ऑर्बिटल प्रक्षेपण के चरण में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा, "इससे पहले हमने मिशन प्रारंभ के तहत "विक्रम-एस" का प्रक्षेपण किया था। अब विक्रम-1 के प्रक्षेपण को मिशन आगमन नाम दिया गया है।" विक्रम-1 को छोटे उपग्रहों को निचली पृथ्वी (लो अर्थ ऑर्बिट) कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में इसकी पेलोड क्षमता 350 किलोग्राम है, जिसे भविष्य के अभियानों में बढ़ाकर 500 किलोग्राम करने की योजना है।

चंदना ने कहा, "विक्रम-1 की अंतिम पेलोड क्षमता 500 किलोग्राम होगी, लेकिन फिलहाल इसे 350 किलोग्राम पेलोड के साथ प्रक्षेपित किया जा रहा है।" यह रॉकेट निम्न पृथ्वी कक्षा में 350 किलोग्राम तथा सूर्य-समकालिक कक्षा (सन-सिंक्रोनस ऑर्बिट) में 260 किलोग्राम तक के उपग्रह स्थापित कर सकता है। यह पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक उपग्रह पहुंचाने में सक्षम है।

भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉ. विक्रम साराभाई का नाम रखा गया है, इसकी इस रॉकेट की ऊंचाई लगभग 20 मीटर और वजन करीब 40 टन है।

चंदना ने बताया, "यह रॉकेट 40 टन वजनी और 20 मीटर ऊंचा है, जो लगभग सात मंजिला इमारत के बराबर है। यह उपग्रहों को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अंतरिक्ष में पहुंचाने में सक्षम है।" स्काईरूट के अनुसार, विक्रम-1 का व्यास 1.7 मीटर है और इसकी थ्रस्ट क्षमता 1,200

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अगले साल से मिलेंगे प्लास्टिक के नोट

नई दिल्ली, 18 जुलाई। भारत में पॉलीमर यानी प्लास्टिक के नोट चलन में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। फिलहाल दस व बीस रुपये के प्लास्टिक नोट बाजार में लाए जाएंगे। इसमें सुरक्षा के उन्हीं उन्नत नियमों का पालन किया जाएगा जो कागज के नोट छापने में अपनाए जाते हैं। अगले साल यह नोट बाजार में आ सकते हैं।

रिजर्व बैंक ने पॉलीमर शीट आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों को भी आमंत्रित किया है। शुरुआती चरण सफल रहा तो बड़े नोट भी चरणबद्ध तरीके से लाए

- रिज़र्व बैंक ने शुरुआत में दस व बीस रु. के प्लास्टिक नोट चलाने का निर्णय लिया है।

जाएंगे। इन पॉलीमर नोटों के लिए डिजाइन, आकार व छपाई उसी तरह होगी जैसे कागज के नोट पर होगी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए इन नोटों में विशेष तकनीक अपनाई जाएगी। वर्ष 2012 में भारत सरकार ने मैसूर, जयपुर, भुवनेश्वर और शिमला समेत कुछ शहरों में 10 रुपये के एक अरब पॉलीमर नोटों के परीक्षण को मंजूरी दी थी।

एनडीए में आना है तो पहले सुनेत्रा पवार की एनसीपी में विलय करना होगा

सूत्रों के अनुसार, भाजपा ने शरद पवार के सामने एनडीए में शामिल होने के लिए शर्त रखी है

- भाजपा शरद पवार की एनसीपी को पृथक इकाई के रुप में एनडीए में लेना नहीं चाहती है। क्योंकि भाजपा को भय है कि अगर वे स्वतंत्र इकाई के रुप में आए तो भविष्य में चुनौती पैदा कर सकते हैं। भाजपा ने ऑफर दिया है कि अगर दोनों गुट एक हो गए तो दोनों से एक-एक नेता को केन्द्र सरकार में मंत्री बनाया जाएगा।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 18 जुलाई। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) चाहती है कि शरद पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी (एसपी) गुट, एनडीए में शामिल होने से पहले सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट के साथ फिर से एक हो जाए। प्रस्तावित परिसीमन विधेयक पर एनसीपी (एसपी) के नरम रुख के संकेत मिलने के बाद इस दिशा में बातचीत ने गति पकड़ ली है।

महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले एक सप्ताह से इस बात की चर्चाएं तेज हैं कि अनुभवी, और अप्रत्याशित राजनीति के लिए चर्चित शरद पवार ने भाजपा के साथ संपर्क साधने के संकेत दिए हैं।

सूत्रों ने कहा कि भाजपा नेतृत्व एनसीपी (एसपी) को अलग इकाई के रूप में एनडीए में शामिल करने के पक्ष में नहीं है। भाजपा चाहती है कि पहले उसका विलय सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में हो और उसके बाद ही वह एनडीए का हिस्सा बने। भाजपा ने यह संभावना भी खारिज कर दी है कि एनसीपी (एसपी) का सीधा विलय भाजपा में किया जाएगा।

भाजपा ने दोनों गुटों के लिए एक प्रस्ताव भी रखा है। यदि दोनों एनसीपी गुटों का एकीकरण होता है, तो भविष्य में दोनों गुटों से एक-एक नेता को केन्द्र सरकार में मंत्री पद दिए जाने पर विचार किया जा सकता है। शिवसेना और एनसीपी में हुये विभाजन के बाद, भाजपा महाराष्ट्र की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। पार्टी को आशंका है कि यदि एनसीपी (एसपी) को अलग दल के रूप में एनडीए में शामिल किया गया, तो मौजूदा सहयोगी दलों में असुरक्षा और अस्थिरता की स्थिति पैदा हो सकती है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है, जब एनसीपी (एसपी) ने संकेत दिए हैं कि वह परिसीमन विधेयक पर अपेक्षाकृत नरम रुख अपना सकती है। केन्द्र सरकार ने इस विधेयक को महिला आरक्षण कानून के क्रियान्वयन से जोड़ रखा है। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है।

जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, एनसीपी (एसपी) का एनडीए में शामिल होना संसद में उसे दो-तिहाई बहुमत के और करीब ले जाएगा। संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत आवश्यक होता है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार अप्रैल में संसद के विशेष सत्र के दौरान परिसीमन विधेयक पारित नहीं करा सकी थी।

लेकिन उसके बाद, संसद का गणित बदल चुका है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद एक अपेक्षाकृत कम चर्चित दल नेशनलिस्ट सिटीजन्सपार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में शामिल हो चुके हैं और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए का समर्थन किया है। वहीं, उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं।

वर्तमान में एनसीपी (एसपी) के लोकसभा में 8 सांसद और राज्यसभा में 1 सांसद हैं।

लेकिन एनसीपी (एसपी) ने अभी तक परिसीमन विधेयक के समर्थन में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। इस सप्ताह की शुरुआत में बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि यदि प्रस्तावित परिसीमन सभी राज्यों में समान रूप से 50 प्रतिशत सीट वृद्धि के आधार पर किया जाता है, तो इसका विरोध करने का "कोई खास कारण नहीं" रहेगा।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या होगा अगर सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का दुखद अंत हो?

अगर आमरण अनशन में सोनम वांगचुक की मृत्यु हो गई तो इसके नतीजे जनभावना व राजनैतिक प्रतिक्रिया पर निर्भर होंगे

- अगर यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा तो उनकी मृत्यु से शांति समर्थक एनजीओ व राजनैतिक समूह एकजुट होकर बड़ी राजनैतिक क्रांति भी ला सकते हैं, जिसे हैंडल करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा।
- वांगचुक की मृत्यु से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि भी खराब हो सकती है क्योंकि उनकी मृत्यु को अन्तर्राष्ट्रीय मीडिया, वैश्विक पर्यावरण संगठन भी प्रमुखता से लेंगे और शांतिपूर्ण आंदोलनों से निपटने की भारत सरकार की नीति की भारी आलोचना हो सकती है।

- सुकुमार साह -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 18 जुलाई। हर गुज़रते घंटे के साथ हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। चूंकि सोनम वांगचुक की लम्बे समय से चली आ रही भूख हड़ताल उनके स्वास्थ्य पर लगातार गहरा असर डाल रही है और इससे भारत एक ऐसे राजनीतिक मोड़ के करीब पहुंच सकता है, जो आने वाले समय की दिशा तय कर सकता है। उनकी मृत्यु केवल एक आंदोलन का अंत नहीं होगी, बल्कि यह नागरिक स्वतंत्रता, सरकार की जवाबदेही और लद्दाख के अनसुलझे भविष्य पर देशव्यापी बहस को जन्म दे सकती है।

आज की स्थिति के अनुसार, सोनम वांगचुक की हालत गंभीर बताई जा रही है। लंबे समय से जारी भूख हड़ताल के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खबरों के मुताबिक, डॉक्टरों ने गंभीर निर्जलीकरण (डिहाइड्रेशन), शरीर में मैटाबॉलिज्म संबंधी गड़बड़ियों और किडनी में संभावित जटिलताओं की चेतावनी दी है। यह भी बताया गया है कि वांगचुक ने आई वी के जरिए तरल पदार्थ और अन्य उपचार लेने से इनकार कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनके स्वास्थ्य की लगातार चिकित्सकीय निगरानी के निर्देश दिए हैं।

यदि तमाम चिकित्सकीय प्रयासों के बावजूद सोनम वांगचुक की मृत्यु हो जाती है, तो इसके व्यापक और गंभीर राजनीतिक तथा सामाजिक परिणाम सामने आ सकते हैं। हालांकि घटनाक्रम किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक सरकार की प्रतिक्रिया और जनता की भावना पर निर्भर करेगा। उनकी मृत्यु के बाद लगभग निश्चित रूप से विपक्षी दल, नागरिक समाज संगठन और अनेक सार्वजनिक हस्तियां केन्द्र सरकार की तीखी आलोचना करेंगी। यह सवाल उठेगा कि क्या सरकार ने उनका अनशन समाप्त कराने के लिए पर्याप्त प्रयास किए और समय रहते उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने में कोई कमी तो नहीं रही। भले ही प्रशासन ने कानून के दायरे में रहकर काम किया हो, राजनीतिक बहस बेहद तीखी होने की संभावना है। सोनम वांगचुक को केवल लद्दाख ही नहीं, बल्कि पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा के क्षेत्र में उनके नवाचारों और फिल्म "थ्री इडियट्स" के लोकप्रिय किरदार से जुड़ी उनकी पहचान के कारण व्यापक सम्मान प्राप्त है। ऐसे में उनकी मृत्यु लद्दाख, दिल्ली, देशभर के विश्वविद्यालय परिसरों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संगठनों के बीच भारी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया और वैश्विक पर्यावरण संगठनों के द्वारा भी इसे व्यापक रूप से प्रमुखता और कवरेज देने की संभावना है। भूख हड़ताल एक गंभीर नैतिक प्रतीकवाद है। ऐसे में यह मामला मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक विरोध के अधिकार से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन सकता है तथा भारत में शांतिपूर्ण असहमति से निपटने के तरीके पर फिर से विश्व की नजरें टिक सकती हैं।

इतिहास बताता है कि कई बार किसी प्रमुख आंदोलनकारी की मृत्यु किसी आंदोलन को कमजोर करने के बजाय और अधिक मजबूत बना देती है। जनभावना के आधार पर सोनम वांगचुक उन मुद्दों के प्रतीक या शहीद के रूप में उभर सकते हैं, जिनके लिए वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार के लिए उनकी मांगों को नज़रअंदाज़ करना और कठिन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में न्यायिक जांच की मांग हो सकती है या जनहित याचिकाएं दायर हो सकती हैं और स्वतंत्र जांच की मांग, संसद में विस्तृत बहस, पुलिस और अस्पताल प्रशासन की भूमिका की समीक्षा तथा लंबे समय तक चलने वाली भूख हड़तालों से निपटने के सरकारी प्रोटोकॉल की पुनर्समीक्षा की मांग भी की जा सकती है।

यदि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण बना रहता है, तो उनकी मृत्यु विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों को उनकी मांगों के समर्थन में एकजुट कर सकती है। वहीं दूसरी ओर, किसी भी प्रकार की हिंसा या अशांति की आशंका को देखते हुए राजनीतिक दलों और सामुदायिक नेताओं द्वारा संयम और शांति बनाए रखने की अपील भी की जा सकती है। क्या यह घटनाक्रम अनिवार्य रूप से पूरे देश में बड़ी उथल-पुथल का कारण बनेगा? इसका उत्तर है, ऐसा होना जरूरी नहीं है। भारत में पहले भी अनशन और आंदोलनों के दौरान लोगों की मृत्यु हुई है और हर मामले का राजनीतिक प्रभाव अलग-अलग रहा है। इसका दायरा कई कारकों पर निर्भर करेगा-मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई, क्या उन्होंने अंत तक उपचार लेने से इनकार किया, प्रशासन ने चिकित्सा संबंधी स्थिति को कितनी पारदर्शिता से संभाला, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज की प्रतिक्रिया कैसी रही तथा आम जनता ने किसकी जिम्मेदारी मानी।

फिलहाल यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सोनम वांगचुक जीवित हैं, चिकित्सकीय निगरानी में हैं और उनके स्वास्थ्य पर लगातार नज़र रखी जा रही है। यद्यिप उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन परिणाम का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है। इसलिए उनकी संभावित मृत्यु को लेकर किसी भी प्रकार की अटकलों को अत्यंत सावधानी के साथ देखा जाना चाहिए।